



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)  
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 53] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 4, 1994/माघ 15, 1915  
No. 53] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 4, 1994/MAGHA 15, 1915

वित्त मंत्रालय  
आर्थिक कार्य विभाग  
(वैकल्पिक प्रभाग)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 1994

सा.का.नि. 62 (अ).—केन्द्रीय सरकार, नीकों और वित्तीय संस्थानों को पोष्य ऋण बसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 36 की उप धारा (2) के खण्ड (क) के साथ पठित धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण बसूली अधिकरण (पीठासीन अधिकारी के वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तों) नियम, 1993 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख की प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

- (क) "अधिनियम" से बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को पोष्य ऋण बसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) अभिप्रेत है ;
- (ख) "पीठासीन अधिकारी" से अधिनियम की धारा 4 के अधीन किसी अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है ;
- (ग) "नियम" से ऋण बसूली अधिकरण (पीठासीन अधिकारी के वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तों) नियम, 1993 अभिप्रेत है ;
- (घ) उन शब्द सभी शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उस अधिनियम में हैं ;

3. वेतन :- किसी अधिकरण के पीठासीन अधिकारी को 5900-200-6700 स्तर के वेतनमान में वेतन का संवाय किया जाएगा :

परन्तु किसी ऐसे व्यक्ति की पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति की दशा में, जो जिला न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुआ है या जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन सेवा में निवृत्त हुआ है और जो पेंशन उपदान, अभिदायी भविष्य-निधि में नियोजक के अभिदा के रूप में कोई सेवानिवृत्ति फायदे या अन्य रूप के सेवानिवृत्ति फायदे प्राप्त कर रहा है या कर चुका है या प्राप्त करने का हकदार हो गया है, ऐसे पीठासीन अधिकारी के वेतन में से उसके द्वारा प्राप्त या प्राप्त की जाने वाली पेंशन या अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक के अभिदाय या किसी अन्य रूप के सेवा निवृत्ति फायदे, यदि कोई हो, की कुल रकम घटा दी जाएगी।

4. प्रतिनियुक्ति छुट्टी भत्ता :- यदि किसी ऐसे व्यक्ति की, जो 5900-200-6700 रुपए के वेतनमान में नियमित आधार पर पद धारण किए हुए हैं, किसी अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति की जाती है, तो उसे नियम 3 में विनिर्दिष्ट वेतनमान में वेतन तथा ऐसी दर से प्रतिनियुक्ति छुट्टी भत्ते का संदाय किया जाएगा, जो समतुल्य वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के समूह "क" अधिकारियों को लागू है।

5. महगाई भत्ता और नगर प्रतिकरात्मक भत्ता :- किसी अधिकरण का पीठासीन अधिकारी ऐसी दर से महगाई भत्ता और नगर प्रतिकरात्मक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा, जो समतुल्य वेतन ले रहे केन्द्रीय सरकार के समूह "क" अधिकारियों को अनुज्ञेय है।

6. छुट्टी :- किसी अधिकरण का पीठासीन अधिकारी छुट्टी की वास्तव अपने अधिकारियों से संबंधित विषयों के बारे में केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 द्वारा शामिल होगा।

7. छुट्टी मंजूरी प्राधिकारी :- किसी अपील अधिकरण का ऐसा पीठासीन अधिकारी, जो अधिकरण की अधिकारिता शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग कर रहा है, ऐसे अधिकरण के पीठासीन अधिकारी को छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।

8. भविष्य निधि :- किसी अधिकरण का पीठासीन अधिकारी साधारण भविष्य निधि या अभिदायी भविष्य निधि में अभिदाय करने का हकदार होगा और यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह पेंशन प्राप्त करने का हकदार है अथवा नहीं। पेंशन के लिये हकदार व्यक्ति, साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम, 1960 तथा अन्य अभिदायी भविष्य निधि (भारत) नियम, 1962 के उपबंधों द्वारा शामिल होंगे। संबंधित सेवा के नियमों के अनुसार, सेवागत न्यायार्थी अथवा आई.एन. एम. के तामील करने वाले सदस्य ही पेंशन प्राप्त करने के हकदार हैं।

9. यात्रा भत्ते :- किसी अधिकरण का पीठासीन अधिकारी दोरे या स्थानान्तरण के दौरान (जिसके अंतर्गत अधिकरण में कार्यभार ग्रहण करने के लिए या अधिकरण से उसकी पदावधि की समाप्ति पर स्वतः जाने के लिए की गई यात्रा भी है) यात्रा भत्ते, दैनिक भत्ते, वैयक्तिक जीवनशैली के परिवहन और ऐसी ही अन्य बातों के संबंध में उसी मापमान और उन्हीं दरों में हकदार होगा, जो समतुल्य वेतन ले रहे केन्द्रीय सरकार के समूह "क" अधिकारियों को लागू है।

10. छुट्टी यात्रा रियायत :- किसी अधिकरण का पीठासीन अधिकारी उन्हीं दरों में और उसी मापमान पर छुट्टी यात्रा रियायत का हकदार होगा, जो समतुल्य वेतन ले रहे केन्द्रीय सरकार के समूह "क" अधिकारियों को लागू है।

11. वाम सुविधा (1) किसी अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, साधारण पूल वाम-सुविधा से, उपलब्धता के अधीन रहने हुए, केन्द्रीय सरकार के ऐसे समूह "क" अधिकारी को अनुज्ञेय टाइटप के सरकारी निवास का जो उस स्थान पर कार्य कर रहा है जहां ऐसा अधिकरण अवस्थित है, और समतुल्य वेतन ले रहा है, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट दरों में अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करने पर, उपयोग करने का पात्र होगा।

(2) जहां किसी अधिकरण का पीठासीन अधिकारी अनुज्ञेय अवधि में परे सरकारी निवास का अधिकार करता है वहां वह, यथास्थिति, अतिरिक्त अनुज्ञप्ति फीस या शास्तिक किराया संदत्त करने का दायी होगा और वह केन्द्रीय सरकार के सेवकों को लागू नियमों के अनुसार भेदबद्ध किए जाने का दायी होगा।

(3) जहां किसी अधिकरण का पीठासीन अधिकारी, उपनियम (1) के अधीन सरकारी निवास को सुविधा का उपभोग नहीं करता है वहां वह अपने मकान किराया भत्ते का हकदार होगा जो समतुल्य वेतन ले रहे केन्द्रीय सरकार के समूह "क" अधिकारियों को अनुज्ञेय है।

12. चिकित्सीय उपचार की सुविधाएं :- किसी अधिकरण का पीठासीन अधिकारी अभिदायी स्वास्थ्य सेवा स्कीम नियम, 1954 में यथा उपबंधित चिकित्सीय उपचार और अस्पताल सुविधाओं का हकदार होगा और ऐसे स्थानों में, जहां केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा स्कीम प्रवर्तन में नहीं है, वहां उक्त पीठासीन अधिकारी केन्द्रीय सेवा चिकित्सा परिवर्षा नियम, 1944 में यथा उपबंधित सुविधाओं का हकदार होगा।

13. अवशिष्टीय उपबंध—किसी अधिकरण के पीठासीन अधिकारी की सेवा जर्न में संबंधित वे मामले, जिनकी बाबत उन नियमों में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, प्रत्येक मामले में केन्द्रीय सरकार को उसके विनिर्णय के

लिए निर्दिष्ट किए जाएंगे और केन्द्रीय सरकार का उन पर विनिश्चय पीठासीन अधिकारी पर प्रावृद्धकर होगा।

14. शिथिल करने की शक्ति केन्द्रीय सरकार का, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की वास्तव शिथिल करने की शक्ति होगी।

[फा.स. 18 (3)/93-समन्वय]  
ए.के. जैन, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 4th February, 1994

### NOTIFICATION

G.S.R. 62(E).—In exercise of the powers conferred by Section 13, read with clause (a) of sub-section (2) of section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Debts Recovery Tribunal (Salaries, allowances and other terms and conditions of Service of Presiding Officer) Rules, 1993.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires:—

(a) 'Act' means the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993);

(b) 'Presiding Officer' means a person appointed as Presiding Officer of a Tribunal under section 4 of the Act;

(c) 'rules' means Debts Recovery Tribunal (Salaries, allowances and other terms and conditions of Service of Presiding Officer) Rules, 1993;

(d) all other words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Salary.—The Presiding Officer of a Tribunal shall be paid a salary in the scale of pay of Rs. 5900-200-6700:

Provided that in the case of an appointment of a person as a Presiding Officer, who has retired as a District Judge, or who has retired from service, under the Central Government or a State Government and who is in receipt of or has received or has become entitled to receive any retirement benefit by way of pension, gratuity, employer's contribution to the Contributory Provident Fund or other forms of retirement benefits, the pay of such Presiding Officer shall be reduced by the gross amount of pension or employers contribution to the Contributory Provident Fund or any other form of retirement benefit, if any, drawn or to be drawn by him.

4. Deputation Duty Allowance.—If a person holding the post on a regular basis in the scale of pay of Rs. 5900-200-6700 is appointed as Presiding Officer of a Tribunal on tenure basis and holds lien in his parent cadre, he shall be paid a salary in the scale of pay specified in rule 3 plus a deputation duty allowance at a rate as are applicable to Group 'A' officers of the Central Government drawing an equivalent pay.

5. Dearness allowance and city compensatory allowance.—The Presiding Officer of a Tribunal shall be entitled to draw dearness allowance and city compensatory allowance at the rate admissible to Group 'A' officers of the Central Government drawing an equivalent pay.

6. Leave.—The Presiding Officer of a Tribunal shall be governed in matters relating to his rights in respect of leave by the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972.

7. Leave sanctioning authority.—The Presiding Officer of an Appellate Tribunal exercising the jurisdiction, powers and authority on the Tribunal shall be the authority competent to sanction leave to the Presiding Officer of such Tribunal.

8. Pension/Provident Fund.—In case a serving Judge or an Officer of the Central Government or State Government is holding the post of Presiding Officer, the service rendered in the Tribunal will count for pension to be drawn in accordance with the rules of the service to which he belongs. He shall also be governed by the provisions of the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960. In all other cases, a person shall be entitled to Contributory Provident Fund (India) Rules 1962.

9. Travelling allowances.—The Presiding Officer of a Tribunal while on tour or on transfer (including the journey undertaken to join the Tribunal or on the expiry of his term with the Tribunal to proceed to his home town) shall be entitled to the travelling allowances, daily allowances, transportation of personal effects and other similar matters at the same scale and at the same rates as are applicable to Group 'A' officers of the Central Government drawing an equivalent pay.

10. Leave travel concession.—The Presiding Officer of a Tribunal shall be entitled to leave travel concession at the same rates and at the same scale as are applicable to Group 'A' officers of the Central Government drawing an equivalent pay.

11. Accommodation.—(1) Every person appointed as a Presiding Officer of a Tribunal shall be eligible, subject to availability, to the use of official residence from the general pool accommodation of the type admissible to a Group 'A' officer of the Central Government who is working at the place where such Tribunal is located and drawing an equivalent pay on payment of the licence fee at the rates specified by the Central Government from time to time.

(2) Where the Presiding Officer of a Tribunal occupies an official residence beyond permissible period, he shall be liable to pay additional licence fee or penal rent, as the case may be and he shall be liable to eviction in accordance with the rules applicable to Central Government Servants.

(3) Where the Presiding Officer of a Tribunal does not avail of facility of official residence under sub-rule (1), he shall be entitled to House Rent Allowance as admissible to Group 'A' officers of the Central Government drawing an equivalent pay.

12. Facilities for medical treatment.—The Presiding Officer of a Tribunal shall be entitled to medical treatment and hospital facilities as provided in the Contributory Health Services Scheme Rules, 1954 and in places where the Central Health Services Scheme is not in operation, the said Presiding Officer shall be entitled to the facilities as provided in the Central Services Medical Attendance Rules, 1944.

13. Residuary provision.—Matters relating to the conditions of services of the Presiding Officer of a Tribunal with respect to which no express provision has been made in these rules, shall be referred in each case to the Central Government for its decision and the decision of the Central Government thereon shall be binding on the said Presiding Officer.

14. Power to relax.—The Central Government shall have power to relax the provisions of any of these rules in respect of any class or categories of persons.

[No. F. 18(3)/93-Coord.]

A. K. JAIN Jr, Secy.

## अधिसूचना

तृदि दिल्ली 4 फरवरी, 1994

सा.का.नि. 63 (अ) :— केन्द्रीय सरकार, बंधों और वित्तीय संस्थाओं का शोधन ऋण बसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 36 की उपधारा (2) के खंड (क) के साथ पठित धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण बसूली अधीन अधिकरण (पीठासीन अधिकारी के वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 1993 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) “अधिनियम” से वेतन और वित्तीय संस्थाओं को शोधन ऋण बसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) अभिप्रेत है ;

(ख) “पीठासीन अधिकारी” से अधिनियम की धारा 9 के अधीन किसी अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(ग) “नियम” से ऋण बसूली अधिकरण (पीठासीन अधिकारी के वेतन, भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 1993 अभिप्रेत है ;

(घ) उन अन्य सभी शब्दों और पदों, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे, जो उस अधिनियम में हैं।

3. वेतन :—किसी अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी को उनका वेतन संयुक्त किया जाएगा जो उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश को अनुज्ञेय है :—

परन्तु किसी ऐसे व्यक्ति की पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति की दशा में, जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुआ है या जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन सेवा से निवृत्त हुआ है और जो पेंशन, उपदान अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक के अभिदाय के रूप में कोई सेवानिवृत्ति फायदे या अन्य रूप के सेवानिवृत्ति फायदे प्राप्त कर रहा है या कर चुका है या प्राप्त करने का हकदार हो गया है ऐसे पीठासीन अधिकारी के वेतन में से उसके द्वारा प्राप्त या प्राप्त की जाने वाली पेंशन या अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक के अभिदाय या किसी अन्य रूप के सेवानिवृत्ति फायदे, यदि कोई हो, की कुल रकम घटा दी जाएगी।

4. मंहगाई भत्ता और नगर प्रतिकरात्मक भत्ता :— किसी अपील अधिकरण का पीठासीन अधिकारी ऐसी दर से मंहगाई भत्ता और नगर प्रतिकरात्मक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अनुज्ञेय है।

5. छुट्टी :—(1) किसी अपील अधिकरण में पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति होने पर कोई व्यक्ति निम्नलिखित रूप में छुट्टी का हकदार होगा :—

(i) सेवा के प्रत्येक संपूरित कलेंडर वर्ष या उसके भाग के लिए तीन दिन की दर से उपाजित छुट्टी ; परन्तु प्रत्येक कलेंडर वर्ष की पहली जनवरी और पहली जुलाई को छुट्टी लेखा में पन्द्रह पन्द्रह दिनों की दो किस्मों में उपाजित छुट्टी अग्रिम रूप में जमा कर दी जाएगी ;

परन्तु यह और कि पूर्ववर्ती छमाही की समाप्ति पर जमा उपाजित छुट्टी इस शर्त के अधीन रहने हुए अगली छमाही में अग्रनीत की जाएगी कि इस प्रकार अग्रनीत छुट्टी तथा छमाही के लिए जमा की गई छुट्टी एक सौ अस्सी दिन की अधिकतम सीमा से अधिक न हो।

(ii) सेवा के प्रत्येक संपूरित वर्ष की बावत बास दिन की दर के चिकित्सीय प्रमाणपत्र या निजी काम के लिए अर्द्धवेतन छुट्टी और अर्द्धवेतन छुट्टी के लिए संयुक्त उपाजित छुट्टी के दौरान अनुज्ञेय छुट्टी संयुक्त के आधे के समतुल्य होगा,

(iii) अर्द्धवेतन पर छुट्टी भारत के राष्ट्रपति के विवेकानुसार पूर्ण वेतन सहित छुट्टी में परिवर्तित की जा सकती, परन्तु यह तब जब कि वह अस्वस्थता के आधार पर ली जाती है और किसी सक्षम कि चिकित्सा प्राधिकारी के चिकित्सीय प्रमाणपत्र द्वारा समर्थित हो ;

(iv) एक पदावधि में वेतन और भत्तों के बिना अधिकतम एक सौ अस्सी दिन की अधिकतम असाधारण छुट्टी।

6. छुट्टी मंजूरी प्राधिकारी :— भारत के राष्ट्रपति अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी को छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे :

7. पेंशन/भविष्य निधि :— यदि पीठासीन अधिकारी का पद किसी सेवारत न्यायाधीश या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा धारित है तो अपील अधिकरण में की गयी उसकी सेवा, जिस सेवा में वह सम्बद्ध है, उसके नियमों के अनुसार पेंशन प्राप्ति के लिए पात्र माना जाएगा। वह व्यक्ति साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा)



नियम, 1960 के उपबंधों द्वारा भी शासित होगा। अन्य सभी मामलों में वह अभिदायी भविष्य निधि (भारत) नियम, 1962 का हकदार होगा।

8. यात्रा भत्ते :—किसी अपील अधिकरण का पीठासीन अधिकारी दौरे या स्थानान्तरण के दौरान (जिसके अंतर्गत अपील अधिकरण में कार्यभार ग्रहण करने के लिए या अधिकरण में उसकी पदावधि की समाप्ति पर स्वतः जाने के लिए को गई यात्रा भी है) यात्रा भत्ते, दैनिक भत्ते, वैयक्तिक चीजबस्त के परिवहन और ऐसी ही अन्य बातों के संबंध में उन्हीं मापमान और उन्हीं दरों में हकदार होगा जो उच्च न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ते) नियम, 1956 में विहित हैं।

9. छुट्टी यात्रा रियायत :—किसी अपील अधिकरण का पीठासीन अधिकारी उन्हीं दरों से और उसी मापमान पर, जो उस राज्य में जिसमें अपील अधिकरण अवस्थित है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को लागू है, छुट्टी यात्रा रियायत का हकदार होगा।

10. सवारों की सुविधा :—किसी अपील अधिकरण का पीठासीन अधिकारी स्टाफ कार और प्रत्येक मास डेढ़ सौ लीटर पेट्रोल या प्रत्येक मास वारतव में उपभोग किए गए पेट्रोल का इनमें से जो भी कम हो हकदार होगा।

11. वाम सुविधा :—(1) किसी अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, साधारण पूल वाम सुविधा में, उपलब्धता के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार के ऐसे समूह "क" अधिकारी को अनुज्ञेय टाईप के सरकारी निवास का जो उस स्थान पर कार्य कर रहा है जहाँ ऐसा अपील अधिकरण अवस्थित है, और समतुल्य वेतन ले रहा है, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट दरों में अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करने पर, उपयोग करने का पात्र होगा।

(2) जहाँ किसी अपील अधिकरण का पीठासीन अधिकारी अनुज्ञेय अवधि से परे सरकारी निवास का उपभोग करता है वहाँ वह यथास्थिति अनिश्चित अनुज्ञप्ति फीस शास्तिक किराया संदेत करने का दायी होगा और वह केन्द्रीय सरकार के सेवकों को लागू नियमों के अनुसार वेदखल किए जाने का दायी होगा।

(3) जहाँ किसी अपील अधिकरण का पीठासीन अधिकारी, उपनियम (1) के अधीन सरकारी निवास की सुविधा का उपभोग नहीं करता है वहाँ वह उतने मकान किराया भत्ते का हकदार होगा जो समतुल्य वेतन ले रहे केन्द्रीय सरकार के समूह "क" अधिकारियों को अनुज्ञेय है।

12. चिकित्सीय उपचार की सुविधाएँ :—किसी अपील अधिकरण का पीठासीन अधिकारी अभिदायी स्वास्थ्य सेवा स्कीम, नियम, 1954 में यथा उपबंधित चिकित्सीय उपचार अस्पताल सुविधाओं का हकदार होगा और ऐसे स्थानों में जहाँ केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा स्कीम प्रवर्तन में नहीं है,

वहाँ उक्त पीठासीन अधिकारी केन्द्रीय येशा चिकित्सीय परिचर्या नियम, 1944 में यथा उपबंधित सुविधाओं का हकदार होगा।

13. अर्वागच्छाय उपक्रम :—किसी अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी की सेवा शर्तों में संबंधित वे मामले, जिनको बावत इन नियमों में कोई अभिव्यक्ति उपबंध नहीं किया गया है, प्रत्येक मामले में केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए निदिष्ट किए जाएंगे और केन्द्रीय सरकार का उन पर विनिश्चय उक्त पीठासीन अधिकारी पर बाधक नहीं होगा।

14. शिथिल करने की शक्ति :—केन्द्रीय सरकार को, इन नियमों के किन्हीं उपबंधों को किसी वर्ग या वर्ग के व्यक्तियों को बावत शिथिल करने की शक्ति होगी।

[फा. सं. 18/3/93 समन्वय]

ए. के. जैन, संयुक्त सचिव

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 4th February, 1994

G.S.R. 63(E).—In exercise of the powers conferred by Section 13, read with clause (a) of sub-section (2) of section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Debts Recovery Appellate Tribunal (Salaries, Allowances and other terms and conditions of service of Presiding Officer) Rules, 1993.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) 'Act' means the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993);

(b) 'Presiding Officer' means a person appointed as Presiding Officer or an Appellate Tribunal under section 9 of the Act;

(c) 'rules' means Debts Recovery Tribunal (Salaries, allowances and other terms and conditions of service of Presiding Officer) Rules, 1993;

(d) all other words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Salary.—The Presiding Officer of an Appellate Tribunal shall be paid such salary as admissible to serving Judge of a High Court:

Provided that in the case of an appointment of a person as a Presiding Officer, who has retired as a Judge of a High Court or who has retired from service under the Central Government or a State Government and who is in receipt of or has received or has become entitled to receive any retirement benefit by way of pension, gratuity, employer's contribution to the Contributory Provident Fund or other forms of retirement benefits, the pay of such Presiding Officer shall be reduced by the gross amount of pension or employer's contribution to the Contributory Provident Fund or any other form of retirement benefit, if any, drawn or to be drawn by him.

4. Dearness allowance and city compensatory allowance.—The Presiding Officer of an Appellate Tribunal shall be entitled to draw dearness allowance and city compensatory allowance at the rate admissible to a Judge of a High Court.

5. Leave.—A person, on appointment as a Presiding Officer in an Appellate Tribunal shall be entitled to leave as follows :

- (i) Earned leave at the rate of thirty days for every completed calendar year of service or a part thereof:

Provided that the leave account shall be credited with earned leave, in advance, in two instalments of fifteen days each on the first day of January and July of every calendar year :

Provided that the leave account shall be credited with the close of previous half year shall be carried forward to the next half year, subject to the condition that the leave so carried forward plus credit for the half year do not exceed the maximum limit of one hundred and eighty days ;

- (ii) Half pay leave on medical certificate or on private affairs at the rate of twenty days in respect of each completed year of service and the leave salary for half pay leave shall be equivalent to half of the leave salary admissible during the earned leave :

- (iii) Leave on half pay may be commuted to full pay leave at the discretion of the President of India, provided it is taken on medical grounds and is supported by a medical certificate by a competent medical authority ;

- (iv) Extraordinary leave without pay and allowances up to a maximum period of one hundred and eighty days in one term of office.

6. Leave Sanctioning Authority.—The President of India shall be the authority competent to sanction leave to the Presiding Officer of the Appellate Tribunal.

7. Pension/Provident Fund.—In case a serving Judge or an Officer of the Central Government or State Government is holding the post of Presiding Officer, the Service rendered in Appellate Tribunal will count for pension to be drawn in accordance with the rules of the service to which he belongs. He shall also be governed by the provisions of the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960. In all other cases, a person shall be entitled to Contributory Provident Fund (India) Rules, 1962.

8. Travelling Allowances.—The Presiding Officer of an Appellate Tribunal while on tour or on transfer (including the journey undertaken to join the Appellate Tribunal or on the expiry of his term with the Appellate Tribunal to proceed to his home town) shall be entitled to the travelling allowances, daily allowances, transportation of personal effects and other similar matters at the same scales and at the same rates as are prescribed in the High Court Judge (Travelling Allowances) Rules, 1956.

9. Leave Travel Concession.—The Presiding Officer of an Appellate Tribunal shall be entitled to leave travel concession at the same rates and at the same scale as are applicable to a Judge of a High Court in the State in which the Appellate Tribunal is located.

10. Facility of conveyance.—The Presiding Officer of an Appellate Tribunal shall be entitled to a staff car and one hundred and fifty litres of petrol every month or actual consumption of petrol per month, whichever is less.

11. Accommodation.—(1) Every person appointed as a Presiding Officer of an Appellate Tribunal shall be eligible, subject to availability to the use of official residence from the general pool accommodation of the type admissible to a Group 'A' officer of the Central Government, who is working at the place where such Appellate Tribunal is located and drawing an equivalent pay on payment of the licence fee at the rates specified by the Central Government from time to time.

(2) Where the Presiding Officer of an Appellate Tribunal occupies an official residence beyond permissible period, he shall be liable to pay additional licence fee or penal rent, as the case may be, and he shall be liable to eviction in accordance with the rules applicable to Central Government Servants.

(3) Where the Presiding Officer of an Appellate Tribunal does not avail of facility of official residence under sub-rule (1), he shall be entitled to House Rent Allowance as admissible to Group 'A' officers of the Central Government drawing equivalent pay.

12. Facilities for medical treatment.—The Presiding Officer of an Appellate Tribunal shall be entitled to medical treatment and hospital facilities as provided in the Contributory Health Services Scheme Rules, 1954 and in places where the Central Health Services Scheme is not in operation, the said Presiding Officer shall be entitled to the facilities as provided in the Central Services Medical Attendance Rules, 1944.

13. Residuary Provision.—Matters relating to the conditions of services of the Presiding Officer of an Appellate Tribunal with respect to which to express provision has been made in these rules shall be referred in each case to the Central Government for its decision and the decision of the Central Government thereon shall be binding on the said Presiding Officer.

14. Power to relax.—The Central Government shall have power to relax the provisions of any of these rules in respect of any class or categories of persons.

[No. F. 18(3)/93-Coord.]

A. K. JAIN, Jr. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1994

सा. का. नि. 64(अ).— केन्द्रीय सरकार बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 36 के खण्ड (2) के उपखण्ड (क) के साथ पठित धारा 7 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों या प्रयोग करने हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(i) इन नियमों का नाम ऋण वसूली अधिकरण (वसूली अधिकारी और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तें) नियम, 1993 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो —

(क) 'अधिनियम' से बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) अभिप्रेत है ;

(ख) "नियम" से ऋण वसूली अधिकरण (वसूली अधिकारी और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तें) नियम, 1993 अभिप्रेत है ;

(ग) उन अन्य सभी शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उस अधिनियम में है।

3. वेतन किसी अधिकरण के बसुली अधिकारी को 3000-100-3500-125-4500-रु. के वेतनमान में वेतन का संदाय किया जाएगा।

4. अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन किसी अधिकरण के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के स्वरूप तथा प्रवर्ग और उनके वेतनमान भट्टी होंगे जो उन नियमों में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।

5. सेवा शर्तों अधिकरण के बसुली अधिकारी और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की वेतन भत्ते, छुट्टी कार्यग्रहण की अवधि, कार्यग्रहण अवधि वेतन, भविष्य निधि, अर्धवर्षिता की प्राप्ति, पेंशन और सेवा निवृत्ति फायदों, चिकित्सीय सुविधाएँ, आचरण, अनुशासनिक मामले और सेवा की अन्य शर्तें ऐसे अन्य नियमों और विनियमों के अनुसार विनियमित होंगी जो केन्द्रीय सरकार के यथास्थिति समूह "क" समूह "ख", "ग" और समूह "घ" के अधिकारियों और कर्मचारियों को समय-समय पर लागू है और जो तत्समान वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं।

#### अनुसूची

क्रम सं.	पद का नाम	वेतनमान
1	2	3
1.	मचिव / रजिस्ट्रार	3950-125-4700-150-5000 रु.
2.	पीठासीन अधिकारी का निजी सचिव	2000-60-2300-द.रो. 75-3200-100 3500 रु.
3.	अनुभाग अधिकारी	2000-60-2300-द.रो. -75-3200-100 3500 रु.
4.	सहायक / अनुसंधान सहायक	1640-60-2600-द.रो. -75-2900 रु.
5.	आशुलिपिक श्रेणी "ग"	1640-60-2600-द.रो. -75-2900 रु.
6.	आशुलिपिक श्रेणी "घ"	1200-30-1560-द.रो. -40-2040 रु.
7.	उच्च श्रेणी लिपिक/रोकड़िया/केयरटेकर	1200-30-1560-द.रो. 40-2040 रु.
8.	निम्न श्रेणी लिपिक/टाईपिस्ट	950-20-1150-द.रो. 25-1500 रु.
9.	स्टाफ कार ड्राइवर	950-20-1150-द.रो. -25-1500 रु.

1	2	3
10.	मेन्टेनर ऑपरेटर	800-15-1010-द.रो. -20-1150 रु.
11.	जमादार / दफतरी	775-12-955-द.रो. -14-1025 रु.
12.	चपरासी/कराग/साइकल	750-12-870-द.रो. -14-940 रु.

[अ. सं. 18 (3) / 93 मसम्भय]

ए. के. जैन, संयुक्त सचिव

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 4th February, 1994

G.S.R. 64(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 7 read with sub-clause (a) of clause (2) of section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993) the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Debts Recovery Tribunal (Salaries, Allowances and other conditions of service of the Recovery Officer and other officers and Employees) Rules, 1993.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) 'Act' means the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993).

(b) 'rules' means Debts Recovery Tribunal (Salaries, Allowance and other conditions of service of the Recovery Officer and other Officers and Employees Rules, 1993;

(c) all other words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Salary.—The Recovery Officer of a Tribunal shall be paid a salary in the scale of pay of Rs. 3000-100-3500-125-4500.

4. Salary of other Officers and Employees of the Tribunal.—The nature and categories of other officers and employees of a Tribunal and the Scales of pay thereof shall be as specified in the Schedule appended to these rules.

5. Conditions of Service.—The conditions of service of the Recovery Officer and other officers and employees of the Tribunal in the matter of pay, allowances, leave, joining time, pension and retirement benefits, medical facilities, conduct, disciplinary matters and other conditions of service, shall be regulated in accordance with such other rules and regulations as are, from time to time, applicable to officers and employees of the Central Government belonging to Group 'A', Group 'B', Group 'C' and Group 'D', as the case may be and drawing the corresponding scales of pay.

## SCHEDULE

S.No.	Name of Post	Scale of Pay
1.	Secretary/Registrar	Rs. 3950-125-4700-150-5000.
2.	Private Secretary to Presiding Officer	Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500
3.	Section Officer	Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500
4.	Assistant/Research Assistant	Rs. 1640-60-2600-EB-75-2900
5.	Stenographer Grade 'C'	Rs. 1640-60-2600-EB-75-2900
6.	Stenographer Grade 'D'	Rs. 1200-30-1560-EB-40-2040
7.	Upper Division Clerk/Cashier/Caretaker	Rs. 1200-30-1560-EB-40-2040
8.	Lower Division Clerk/Typist	Rs. 950-20-1150-EB-25-1500
9.	Staff-Car Driver	Rs. 950-20-1150-EB-25-1500
10.	Gestetner Operator	Rs. 800-15-1010-EB-20-1150
11.	Jamadar/Daftry	Rs. 775-12-955-EB-14-1025
12.	Peon/Farash/Sweeper	Rs. 750-12-870-EB-14-940

[F.No. 18(3)/93-Coord]

A.K. JAIN, Jt. Secy.

## सधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1994

भा. का. नि. 65(प्र):— केन्द्रीय सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम 1993 (1993 का 51) की धारा 36 के खंड (2) के उपखंड (क) के साथ पठित धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:— (1) इन नियमों का नाम ऋण वसूली अपील अधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तों) नियम, 1993 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं:— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:—

(क) "अधिनियम" से बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) अभिप्रेत है;

(ख) "नियम" से ऋण वसूली अपील अधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तों) नियम, 1993 अभिप्रेत है;

(ग) उन अन्य सभी शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं

किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

3. अपील अधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन:—अपील अधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के स्वरूप तथा प्रवर्ग और उनके वेतनमान बढ़ी होंगे जो इन नियमों से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।

4. सेवा शर्तें:—अपील अधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की वेतन, भत्ते, छुट्टी, कार्य ग्रहण की अवधि, कार्यग्रहण अवधि वेतन, भविष्य निधि, अधिवर्षिणा की प्राप्ति, पेंशन और सेवानिवृत्त फायदों, निवृत्तीय भुविप्राप्ति और अन्य सेवा शर्तें ऐसे नियमों और विनियमों के अनुसार विनियमित होंगी जो केन्द्रीय सरकार के, यथास्थिति समूह "क", समूह "ख", समूह "ग" और समूह "घ" के अधिकारियों और कर्मचारियों को समय-समय पर लागू हैं और जो तत्समान वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं।

## अनुसूची

क्रम सं. पद का नाम	वेतनमान
1. सचिव/रजिस्ट्रार	3950-125-4700-150-50000 रु.
2. पीठासीन अधिकारियों का निजी सचिव	2000-60-2300-द. रो. 75-3200-100-35000 रु.



क्रम सं.	पद का नाम	वेतनमान
3.	अनुभाग अधिकारी	2000-60-2300-द.रो. 75-3200-100-3500 रु.
4.	सहायक/अनुसंधान सहायक	1640-60-2600-द.रो. 75-2900 रु.
5.	आशुलिपिक श्रेणी "ग"	1640-60-2600-द.रो.- 75 2900 रु.
6.	आशुलिपिक श्रेणी "घ"	1200-30-1560-द.रो.- 40-2040 रु.
7.	उच्च श्रेणी लिपिक/रोकडिया/ केयरटेकर	1200-30-1560-द.रो.- 40-2040 रु.
8.	निम्न श्रेणी लिपिक/टाइपिस्ट	950-20-1150-द.रो.- 25-1500 रु.
9.	स्टाफ कार ड्राइवर	950-20-1150-द.रो.- 25-1500 रु.
10.	अमादार/दफ्तरी	775-12-955-द.रो.-14- 1025 रु.
11.	चपरासी/फराश/साइकल	750-12-870-द.रो.- 14-940 रु.

[सं. एक 18 / 3 / 93 समन्वय]

ए. के. जैन, संयुक्त सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 4th February, 1994

G.S.R. 65(E).—In exercise of the powers conferred by section 12, read with sub-clause (a) of clause (2) of section

## SCHEDULE

S.No.	Name of Post	Scale of Pay
1.	Secretary/Registrar	Rs. 3950-25-4700-150-5000
2.	Private Secretary to Presiding Officer	Rs. 2000-60-2300-EB-75-2300-100-3500
3.	Section Officer	Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500
4.	Assistant/Research Assistant	Rs. 1640-60-2600-EB-75-2900
5.	Stenographer Grade 'C'	Rs. 1640-60-2600-EB-75-2900
6.	Stenographer Grade 'D'	Rs. 1200-30-1560-EB-40-2040
7.	Upper Division Clerk/Cashier/Caretaker	Rs. 1200-30-1560-EB-40-2040
8.	Lower Division Clerk/Typist	Rs. 950-20-1150-EB-25-1500
9.	Staff Car Driver	Rs. 950-20-1150-EB-25-1500
10.	Jamadar/Daftry	Rs. 775-12-955-EB-14-1025
11.	Peon/Farash/Sweeper	Rs. 750-12-870-EB-14-940

[No.F, 18/3/93:Coord]

A.K. JAIN, Jt. Secy.

306 GI/94—2

36 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Debts Recovery Appellate Tribunal (Salaries, allowances and other conditions of Service of the officers and employees) Rules, 1993.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) 'Act' means the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993);

(b) 'rules' means the Debts Recovery Appellate Tribunal (Salaries, allowances and other conditions of service of officers and employees) Rules, 1993;

(c) All other words and expression used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Salary of Officers and employees of the Appellate Tribunal.—The nature and categories of officers and employees of an Appellate Tribunal and the scales of pay thereof shall be as specified in the Schedule appended to these rules.

4. Conditions of service.—The conditions of service of the officers and employees of an Appellate Tribunal in the matter of pay, allowances, leave, joining time, joining time pay, provident fund, age of superannuation, pension and retirement benefits, medical facilities, and other conditions of service, shall be regulated in accordance with such other rules and regulations as are, from time to time, applicable to officers and employees of the Central Government belonging to Group 'A', Group 'B', Group 'C' and Group 'D' as the case may be, and drawing the corresponding scales of pay.

